Sixth Five Year Plan and that for the flrst year of the Seventh Five Year Plan?,

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BUTA SINGH): (a) and (b) According to the studies made by the Programme Evaluation Organisation of the Planning Commission and the National Bank for Agriculture and Rural Development 49 per cent and 47 per cent respectively of the sample households, had crossed the poverty line taken at Rs. 3500/-. 88 per cent and 82 per cent respectively had gol incremental income. Specific numbers that have crossed the poverty line in each State are not available.

c) There was an allocation of Rs. 250.55 crores during 1980-81 for IRDP, ln the ^st y[ei]*r of Seventh Five Year Plan, viz. 1985-86 the allocation (Centre and State) was Rs. 407.36 crores.

Allotment of surrendered/Excess flats in South Delhi by Delhi Development Authority

387. SHRI SHANKER SINH VAGHELA:
SHRI KAILASH PATI MISHRA:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether a large number of al lottees of Sidhartha E\tension, Vasant Vihar and JNU Self-Financing pockets •were not considered for allotment of surrendered, excess flats in South Delhi like East ol Kailash, Gautam Nagar, Alaknanda and Kalkaji instead these flats were offered to those who had been allotted flats in East, West and North Delhi by DDA;

(b) the names of such allottees and the details of the flats so allotted in South Delhi; and

(c) whether any action has been taken againsl the concerned officials, *it* so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) Information is being collected and wi'^1 be laid on the Table of the Sabha.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के विरुद्ध चोरी, धोखाधड़ी आदि के मामले

388. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के ऐसे कर्मचारियों की, श्रेणीवार संख्या कितनी है, जिनके विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान चोरी, धोखाधड़ी तथा अन्य प्रकार के मामले दर्ज किए गए तथा विभाग के पास ऐसे कितने मामले लंबित पड़े हुए हैं; और कब से लम्बित पड़े हुए हैं ;

(ख) इन मामलों को अब तक अंतिम रूप से हल कर लिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने-कितने रुपये की कौन-कौन सी वस्तुएं चोरी से गुम हुई ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा समापटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ठेकेदारों को काली सूची में डाला जाना

389. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्य में गड़बड़ी करने के आरोपों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने ठेकेदारों को काली सूची में डाला गया है, और

(ख) इनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) 1.1.83 से ब्यौरे इस प्रकार हैं :--

(क) घटिया कार्य के लिए वारित ठेकेदार	32
(ख) सीमेन्ट और बिटूमन की चोरी के लिए वारित	8
(ग) घटिया कार्यों के लिए चेतावनी जारी की गई	2
(घ) कार्य आरम्भ न करने पर वारित	1
(ङ) ठेकों के उपबन्धों का उल्लंघन करके निर्माण कार्य प्राप्त करने पर वारित	3

आनन्द स्थित ग्रामीण संस्थान का कार्यकरण

390. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आनन्द स्थित ग्रामीण संस्थान जो एक केन्द्रीय योजना है और जिसे स्विटजरलैण्ड से 789 लाख रुपये फोर्ड फाउन्डेशन से 20 लाख रुपये की विदेशी सहायता तथा भारत सरकार से 107 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, की गतिविधियों के क्षेत्र कौन-कौन से हैं ;

(ख) इस संस्थान ने अब तक 267 स्नातकों को डिप्लोमे दिये हैं और 65 विद्यार्थी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण ले रहे हैं ।

(ख) क्या यह संस्थान डिप्लोमे भी देता है और क्या ये डिप्लोमे 198 अभ्यार्थियों को दिये जा चुके हैं और क्या 135 अभ्यार्थी यहां पर पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण ले रहे हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के अध्ययनों की व्यवस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या कोई अन्य कृषि विश्वविद्यालय नहीं कर सकता; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि इस संस्थान के "बोर्ड आफ गवर्नर्स" में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या किसी कृषि विश्वविद्यालय या उत्तर प्रदेश और बिहार का कोई विद्वान नहीं है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मकवाणा): (क) ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान, आनन्द, जो समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक स्वायत्त निकाय है, की स्थापना ग्रामीण समुदाय के आर्थिक और सामाजिक विकास में लगी सहकारी समितियों और अन्य ग्रामीण उत्पादक संगठनों के लिये शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श के लिये सुविधाओं का सृजन करने और आपरेशन फलड़ की प्रशिक्षित जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं के लिए की गई थी ।

संस्थान के लिये वित्तीय सहायता देने की निम्न पद्धति स्वीकृत की गई थी :--

(लाख रुपयों में)

(1) आपरेशन फलड 2 परियोजना	50.00
(2) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से अंशदान	50.00
(3) फोर्ड फाउन्डेशन अनुदान	20.00
(4) स्विस सरकार से सहायता	789.40
(5) ग्रामीण प्रबंध संस्थान, आनन्द द्वारा वहन किया जाने वाला उपकरण संबंधी आयात शुल्क, यदि कोई हो ।	7.35
कुल :	916.75

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् मूलत: कृषि अनुसंधान का कार्य करती है। कृषि विश्वविद्यालय राज्य स्तर के संस्थान